UPSC-CSE 2027/28
DAILY
CURRENT AFFAIRS
ONE STOP SOLUTION
By Faiyaz Sir
The Indian EXPRESS
THE HINDU
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
04
SEPTEMBER
COMPLETE COVERAGE
EXAM FOCUSED
ANALYSIS MADE EASY
STATIC + CURRENT INTEGRATION
STAY AHEAD
STAY PREPARED

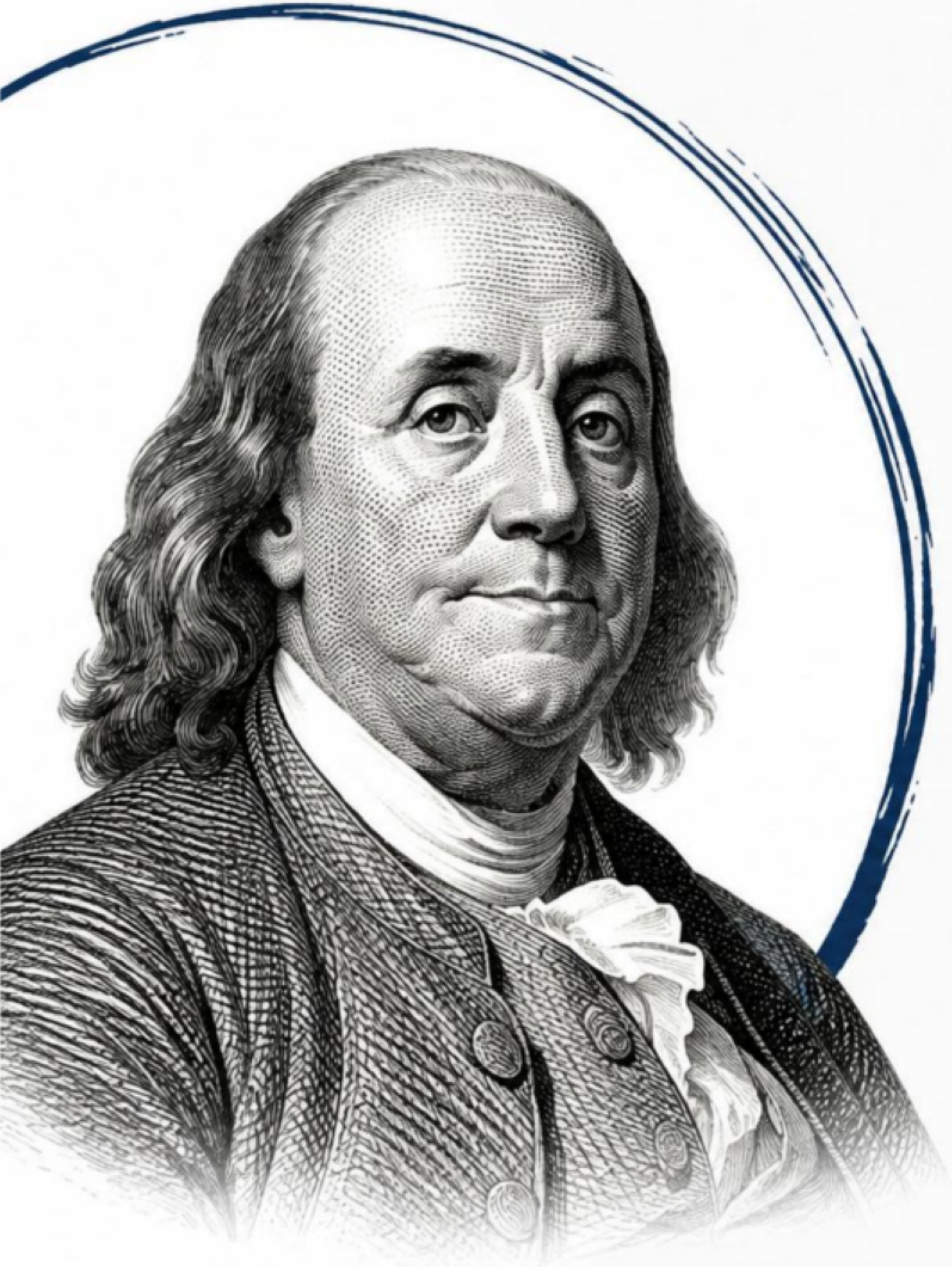

“

ज्ञान में निवेश हमेशा सबसे अच्छा ब्याज देता है।

– Benjamin Franklin

आज क्या पढ़ेंगे?

1. सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना – Economics + Governance Polity
2. जागरूकता से स्वामित्व तक – Geography + Ecology
3. महत्वपूर्ण तथ्य

भारत सरकार
पत्र सूचना कार्यालय

हमारे बारे में · प्रेस विज्ञप्ति · गैलरी · अनुसंधान इकाई · मीडिया सुविधाएं · आर्काइव · तथ्यों की जांच · उन्नत खोज

होम / सभी विश्लेषक / व्याख्यात्मक विवरण

किसान कल्याण

सहकारिता क्षेत्र में विकेंद्रित अनाज भंडारण योजना

"भारत के विकेंद्रित अनाज भंडारण का सुदृढ़ीकरण"

AMUL

31 मई - 2023

2026

मूल्यांकन

सहकारिता

Cooperative

सहकारिता

सूची — राज्य — समवर्ती

संविधान

97th C.A.A - 2011

3

19(1)(c)

4

43-B

9-B

चर्चा में क्यों?

भारत के बढ़ते कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रयासों ने देश भर में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे के महत्व को काफी बढ़ा दिया है। वर्ष 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से भंडारण, प्रसंस्करण, खरीद और वितरण प्रणालियों में सुधार करना है। यह योजना विभिन्न सरकारी पहलों को एकीकृत करके और संस्थागत समर्थन प्रदान करके कार्य करती है।

भंडारण क्षमता का सृजन और कृषि अर्थव्यवस्था का विकास • भारत की पारंपरिक भंडारण प्रणालियों में कोठार, साइलो, मिट्टी के बर्तन, भूमिगत भंडारण और मिट्टी से लेपित संरचनाएं शामिल हैं।

खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा

तृतीय अग्रिम अनुमान (2025-26)

देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 376.563 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष के 357.732 मिलियन टन से 18.8 मिलियन टन (5.3 प्रतिशत) अधिक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाता है, जिसके दायरे में लगभग 80 करोड़ लोग आते हैं।

विकेन्द्रीकृत सुविधाओं की आवश्यकता

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रबंधित केंद्रीयकृत बुनियादी ढांचे के अलावा उत्पादन केंद्रों के पास विकेन्द्रीकृत सुविधाएं होना अत्यंत आवश्यक है।

योजना के उद्देश्य (Objectives)

1 खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना

खाद्य बर्बादी को कम करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना।

2 उचित मूल्य दिलाना

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें औने-पौने दामों पर बेचने (Panic Selling) से बचाने के विकल्प प्रदान करना।

3 परिवहन लागत कम करना

खरीद केंद्रों, गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच परिवहन लागत को कम करना।

4 PACS की भूमिका का विस्तार

कृषि गतिविधियों के विविधीकरण के माध्यम से PACS की भूमिका का विस्तार करना (PACS अल्पकालिक ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली ग्रामीण स्तर की संस्थाएं हैं)।

एकीकृत बुनियादी ढांचा और अभिसरण ढांचा

किसानों के लिए उच्च आय के अवसरों को बढ़ावा देना।

यह योजना निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से PACS स्तर पर एकीकृत कृषि बुनियादी ढांचा तैयार करती है:

कृषि बुनियादी ढांचा कोष (AIF) योजना

फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तपोषण और ब्याज में छूट प्रदान करती है।

कृषि विपणन बुनियादी ढांचा योजना (AMI)

खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए पिछवाड़े (back-ended) पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।

अभिसरण ढांचा और प्रमुख सुविधाएं

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करती है और कृषि मशीनरी तक पहुंच को आसान बनाती है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के औपचारिकरण और विकास को बढ़ावा देती है।

योजना के तहत प्रमुख सुविधाएं और सेवाएं

कस्टम हायरिंग सेंटर

किसानों को किराए पर देने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनरी खरीदने में मदद करते हैं।

उचित मूल्य की दुकानें

स्थानीय समुदायों के भीतर अनाज के वितरण और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बिक्री में सहायता करती हैं।

प्रमुख सुविधाएं और PACS का चयन

प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां

अनाज की सफाई जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण कार्य करती हैं, जिससे उपज की गुणवत्ता और बाजार में उसकी मांग बढ़ती है।

खरीद केंद्र

राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम के लिए PACS द्वारा अनाज की खरीद में मदद करते हैं।

साइलो-आधारित/भंडारण बुनियादी ढांचा योजना

सहकारी भंडारण मॉडल के तहत 50 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन और 200 मीट्रिक टन क्षमता के साइलो/गोदाम स्थापित किए जाते हैं।

PACS का चयन और संस्थागत ढांचा

"गढ़िखड़ी" (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार, जिला सहकारी विकास समितियों द्वारा PACS की पहचान की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

पायलट परियोजना से विस्तार तक की यात्रा

1 पायलट चरण

11 राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, कर्नाटक और त्रिपुरा) के 11 PACS में गोदाम निर्माण पूरा किया गया, जिससे 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित हुई।

2 जुलाई 2026 तक की प्रगति

जुलाई 2026 तक 1,012 PACS की पहचान की जा चुकी है, और 313 PACS में गोदाम निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 1.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक की भंडारण क्षमता सृजित हुई है।

सहकारी गोदाम का सफल उदाहरण: नेरपिंगलाई PACS

3000

मीट्रिक टन क्षमता

महाराष्ट्र के अमरावती स्थित नेरपिंगलाई PACS ने विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत 3,000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है।

300

किसान लाभान्वित

यहाँ लगभग 300 किसान सोयाबीन के लगभग 32,000 बोरे भंडारित कर रहे हैं।

4.50Cr

अग्रिम ऋण

इस सोसायटी ने भंडारित उपज के एवज में लगभग 4.50 करोड़ रुपये का अग्रिम ऋण प्रदान किया है, जिससे किसानों को कम कीमतों पर उपज बेचने के लिए मजबूर होने से बचाया गया है।

इस गोदाम से PACS को प्रति वर्ष लगभग 7.68 लाख रुपये किराये की आय और लगभग 54 लाख रुपये ब्याज आय होने की उम्मीद है।

गुणवत्ता मानक, ब्रांडिंग और पारदर्शिता

समान ब्रांडिंग

प्रत्येक भंडारण संरचना पर स्वीकृत "ग्रेन स्टोरेज लोगो" और निर्धारित रंग योजना प्रदर्शित की जानी चाहिए।

गुणवत्ता आश्वासन

भंडारण संरचनाएं भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA) के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिनमें अनाज के खराब होने से बचाने के लिए उचित वेंटिलेशन हो।

पारदर्शिता

नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता ऑडिट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (PMCs) द्वारा निर्माण गतिविधियों व व्यय के अपडेट साझा किए जाते हैं।

UPSC PYQ

भारत में, प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 2020

1. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (DCCBs), PACS को ऋण सहायता प्रदान करते हैं।
2. PACS ग्रामीण स्तर पर सीधे किसानों से जुड़ी हुई त्रिस्तरीय (3-tier) सहकारी ऋण संरचना की अंतिम कड़ी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1	(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों	(D) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना भारत की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को सुदृढ़ करने में किस प्रकार सहायक है? इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों, अभिसरण ढांचे और वित्तीय प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

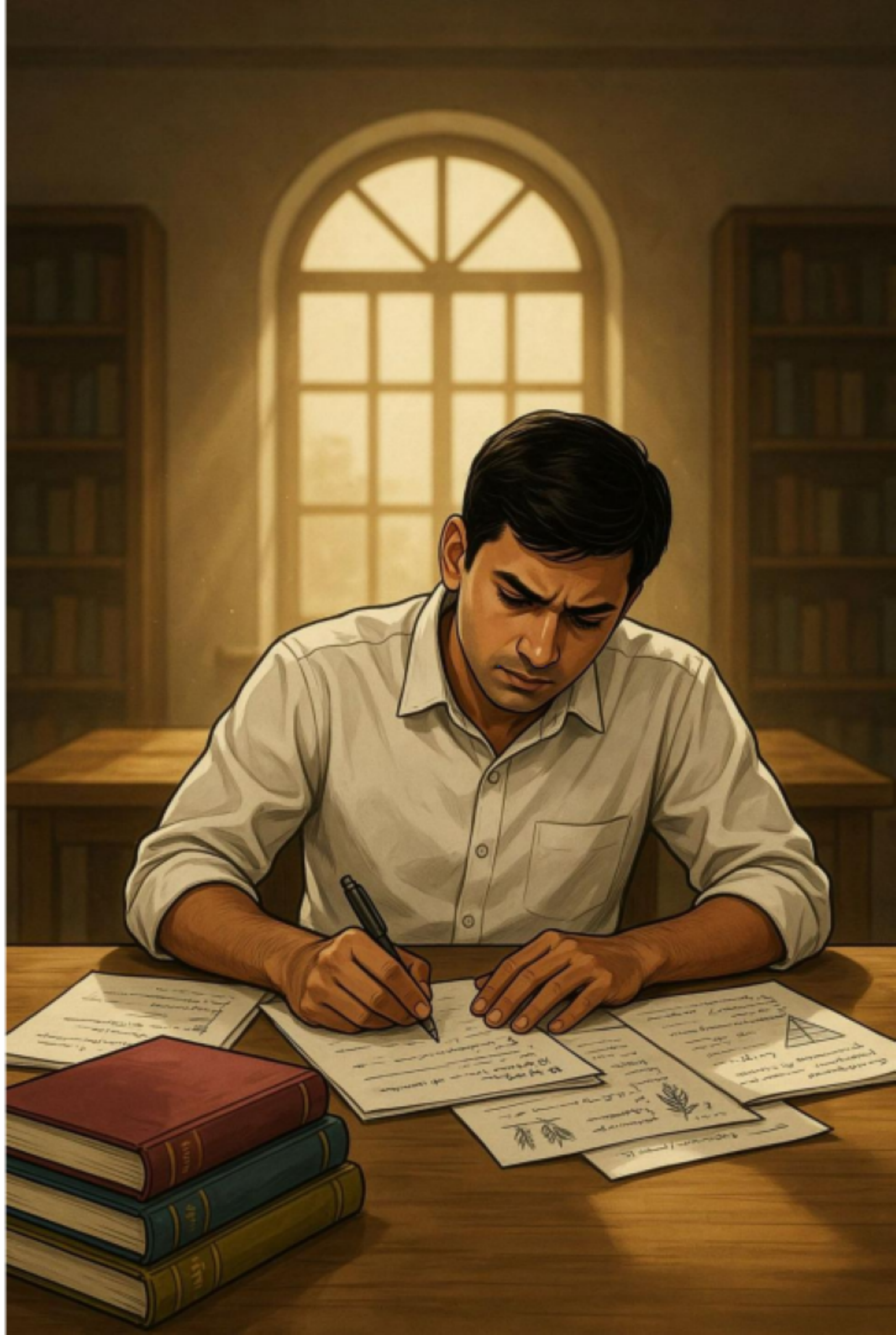

भारत सरकार
पत्र सूचना कार्यालय

हमारे बारे में | प्रेस विज्ञप्ति | गैलरी | अनुसंधान इकाई | मीडिया सुविधाएं | आर्काइव | तथ्यों की जांच | उन्नत खोज

होम / सभी विशेषताएं / विशेषताएं विवरण

Infrastructure

जागरूकता से स्वामित्व तक

नदी संरक्षण के लिए जन-आंदोलन खड़ा करना

नदी संरक्षण

चर्चा में क्यों?

'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत 'जन गंगा' और जन-भागीदारी जैसी पहलों के माध्यम से नदी संरक्षण को केवल सरकारी अभियानों तक सीमित न रखकर इसे सामुदायिक स्वामित्व और एक व्यापक जन-आंदोलन में बदला जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों?

- नमामि गंगे योजना (Namami Gange Programme) जून **2014** में शुरू की गई थी।

मुख्य बातें:

- **उद्देश्य:** गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना, उसकी स्वच्छता और उसके संरक्षण (Rejuvenation) को बढ़ावा देना।
- **मंत्रालय:** यह जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के तहत एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- **कार्यान्वयन:** इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और राज्य स्तरीय संगठनों द्वारा लागू किया जाता है।

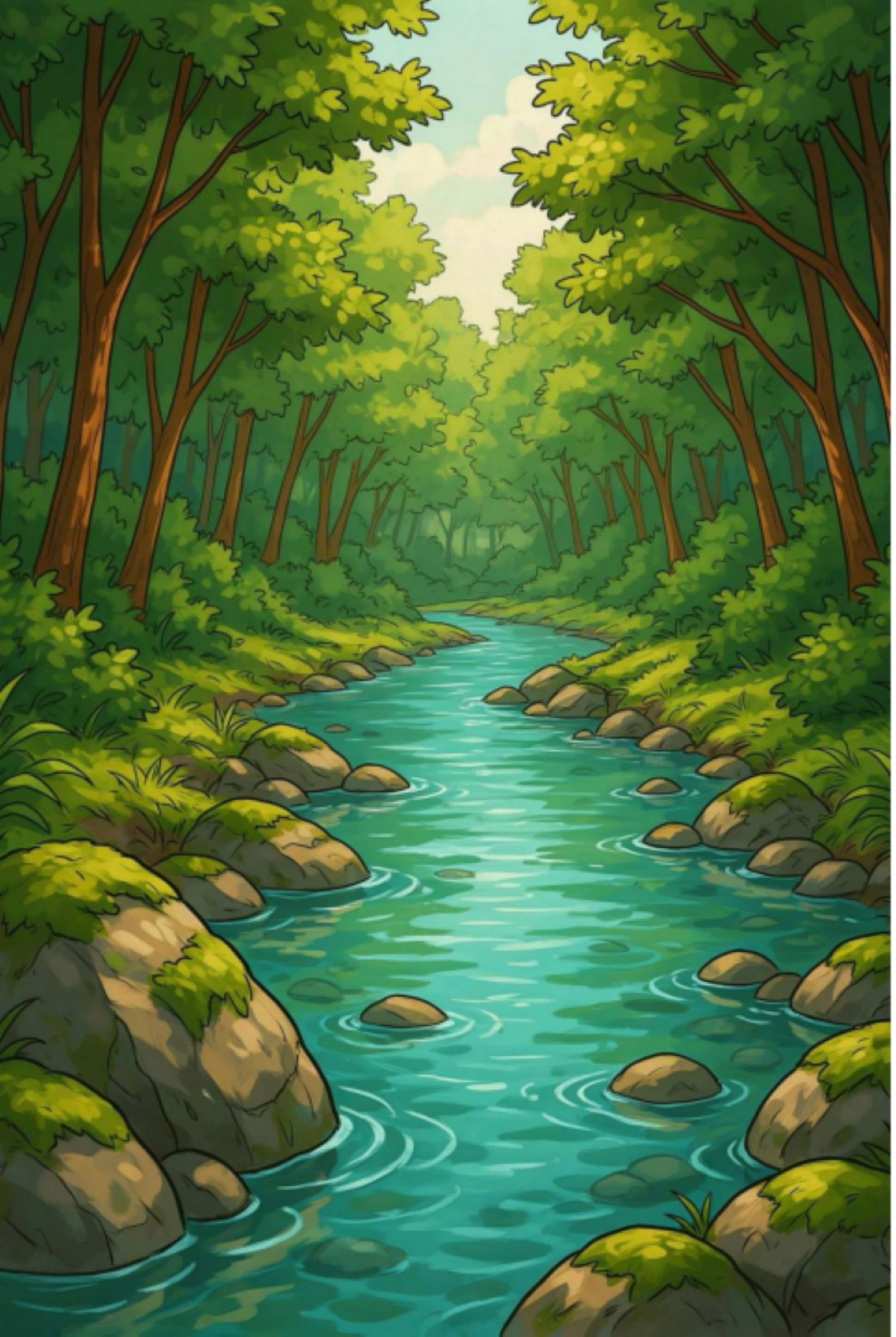

अविरलता और निर्मलता

नदी के प्राकृतिक प्रवाह (अविरलता) और स्वच्छ जल (निर्मलता) को पुनः स्थापित करने तथा लोगों के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी।

नमामि गंगे के मुख्य स्तंभ और जन-भागीदारी

सीवेज शोधन बुनियादी ढांचा: शहरी गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया जा रहा है।

नमामि गंगे के मुख्य स्तंभ

नदी तटीय विकास और सतह सफाई

घाटों, शवदाह गृहों का आधुनिकीकरण तथा मशीनों व मैन्युअल माध्यमों से तैरते हुए कचरे को हटाना।

जैव-विविधता संरक्षण और वनीकरण

गांगेय डॉल्फिन, कछुओं जैसी प्रजातियों की रक्षा और नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से भू-क्षरण रोकना।

जन-भागीदारी स्तंभ ('जन गंगा')

स्थायी बदलाव के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी को इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया गया है, जो लोगों को संरक्षण के केंद्र में रखता है।

गंगा डॉल्फिन

जागरूकता से स्वामित्व तक का सफर: जन-आंदोलन की आवश्यकता क्यों?

स्थायित्व

सरकारें और एजेंसियां केवल बुनियादी ढांचा बना सकती हैं, लेकिन उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वच्छता नागरिकों के सहयोग बिना असंभव है।

व्यवहार परिवर्तन

नदी संरक्षण के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए धार्मिक अनुष्ठानों के तरीकों में बदलाव, प्लास्टिक का त्याग और आंतरिक चेतना का विकास जरूरी है।

जन-भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलें

गंगा प्रहरी और गंगा सेवा दूत: स्थानीय युवाओं और महिलाओं का यह स्वयंसेवी बल जैव-विविधता संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करता है।

अर्थ गंगा

नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी के दायरे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और नदी में रासायनिक खाद का बहाव रुकता है।

गंगा स्वच्छता पखवाड़ा और घाट पर हाट

प्रतिवर्ष मार्च में आयोजित होने वाला पखवाड़ा जन-जन तक स्वच्छता संदेश पहुंचाता है, जबकि 'घाट पर हाट' स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आर्थिक मंच प्रदान करता है।

'एक पेड़ मां के नाम' और युवा सहभागिता

वृक्षारोपण को भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ-साथ स्कूलों और 'विश्वविद्यालय गंगा क्लब' के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जा रहा है।

विद्यमान चुनौतियाँ

प्रशासनिक समन्वय की कमी

केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच तालमेल का अभाव।

ठोस कचरा प्रबंधन

एसटीपी होने के बावजूद शहरी ठोस अपशिष्ट और सिंगल-यूज प्लास्टिक का नालों के जरिए नदियों में लगातार पहुंचना।

पर्यावरणीय प्रवाह का संकट

पर्यावरणीय प्रवाह का संकट: उद्योगों और कृषि के लिए अत्यधिक जल दोहन के कारण नदियों में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखना एक बड़ी बाधा है।

आगे की राह

विकेंद्रीकृत शासन

जिला गंगा समितियों (DGCs) को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंपे जाएं ताकि जमीनी स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सकें।

अपशिष्ट से धन

उपचारित मलजल को उद्योगों और कृषि के लिए उपयोग करने के मॉडल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना।

UPSC PYQ

Q. केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं? (UPSC 2016)

1. राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण निवारण, संरक्षण और कायाकल्प।
2. रोजगार पैदा करने के लिए नदी के किनारों पर 100 किलोमीटर लंबा औद्योगिक गलियारा बनाना।
3. नदी के किनारे स्थित गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 'गंगा ग्राम' का विकास करना।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains Question)

"नदी संरक्षण अभियानों की दीर्घकालिक सफलता केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निर्भर नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए जन-मानस में 'जागरूकता से स्वामित्व' का भाव आना अनिवार्य है।"नमामि गंगे कार्यक्रम के 'जन गंगा' और 'अर्थ गंगा' स्तंभों के विशेष संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(250 शब्द, 15 अंक)

महत्वपूर्ण तथ्य

A CRPF officer during a search conducted by the ED at a home in Kozhikode on Thursday. K. RAGESH

ED launches drive against narcotics in southern States

ED – मादक पदार्थों

Devesh K. Pandey
NEW DELHI

In a major crackdown, the Enforcement Directorate (ED) on Thursday conducted searches at 30 locations across Tamil Nadu, Keralam, Karnataka, and Telangana in connection with eight narcotics-related cases. The agency sources said the operation was linked to the national Nasha Mukt Bharat Abhiyan for a drug-free India.

The searches are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

In Tamil Nadu, the ED is probing the money-laundering angle pertaining to a case in which the Narcotics Control Bureau (NCB) intercepted N. Ajanthan and K. Madhushan, Sri Lankan nationals residing at the Mandapam Camp for refugees in Ramanathapuram, on June 11, 2024. About 1.47 kg of methamphetamine was seized by the NCB.

Sri Lankan links

The records *prima facie* revealed an arrangement in which different persons handled procurement and financing of meth, its transportation, and onward delivery to Sri Lanka.

"The mechanism was supervised remotely, with instructions relayed through the 'Sacha' WhatsApp group, and cash delivered against currency note tokens," an official said, adding that premises in Chennai and Ramanathapuram were searched.

In another Tamil Nadu case, the NCB intercepted Bysul Rahman in Chennai on July 24, 2024, and seized 5.97 kg of meth. It is alleged that the contraband was being sent to Sri Lanka. Another accused, Syed Ibrahim, was linked to Bysul Rahman and K. M. Mansoor, and had allegedly played a role in arranging or financing the transaction. The NCB further impounded ₹39.38 lakh in cash, 586 gm of gold, and 1 kg of silver. The ED searched two locations in Ramanathapuram and Tirunelveli in the case.

The Karnataka case is linked to Mruthyunjaya alias Jayanna, who was apprehended in 2022 with 1.005 kg of hashish oil and 1.2 kg of ganja, estimated to be worth around ₹90 lakh. The ED is probing the proceeds generated from the alleged drug trade and searched three premises in Kolar, Malur, and Hoskote.

In Telangana, the operation covers the FIRs against accused Kalapathi Nithu Bai and others.

Three immovable properties in the name of the main accused are under the scanner.

One Keralam case allegedly involves Ayush Vinod, who was arrested by the State police with 1.366 kg of hybrid ganja. The ED has identified accused Jagath K.M. for his allegedly role in handling the financial side of the operation. Four premises were searched in Kochi and adjoining areas.

YouTube Homework

- ED = June + July
- PMLA
- MANAS

महत्वपूर्ण तथ्य

- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)** भारत सरकार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य देश में युवाओं और समाज को नशीले पदार्थों (Drugs and Substance Abuse) के दुष्प्रभावों से बचाना और भारत को नशा मुक्त बनाना है।

1. नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan)

- **शुरुआत:** 15 अगस्त 2020
- **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)
- **फोकस क्षेत्र:** देश के सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों से शुरू होकर अब यह पूरे देश में लागू है।
- **मुख्य घटक:**
    - **जन जागरूकता (Awareness):** स्कूलों, कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों में युवाओं और महिलाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाना।
    - **साम्युनिटी आउटरीच:** एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), और नेहरू युवा केंद्र (NYKS) जैसे युवा संगठनों की सक्रिय भागीदारी।
    - **उपचार और पुनर्वास:** प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श और इलाज से जोड़ना।

2. नशा मुक्ति के लिए सरकारी ढांचा (Government Structure)

- भारत में नशा नियंत्रण और पुनर्वास का काम दो मुख्य स्तरों पर होता है—**कानूनी/नियंत्रण ढांचा** और **सामाजिक पुनर्वास ढांचा**:

A. सामाजिक एवं पुनर्वास ढांचा (Rehabilitation & Welfare)

- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE):** यह मंत्रालय नशा पीड़ितों के पुनर्वास, परामर्श, इलाज और सामाजिक एकीकरण (Reintegration) के लिए नीतियां और योजनाएं बनाता है।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD):** नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं (Counselors) को प्रशिक्षण (Training) प्रदान करता है।

B. कानून एवं प्रवर्तन ढांचा (Law & Enforcement)

- **गृह मंत्रालय (MHA):** अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री को रोकने के लिए जिम्मेदार।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** देश की शीर्ष केंद्रीय एजेंसी जो NDPS Act (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) के तहत अवैध ड्रग्स की तस्करी और व्यापार पर कार्रवाई करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 3. प्रमुख सरकारी योजनाएं और पहल (Key Schemes & Initiatives)

योजना / पहल	विवरण & उद्देश्य
NAPDDR (राष्ट्रीय मादक द्रव्य मांग कटौती कार्य योजना)	नशा पीड़ितों के इलाज, जागरूकता, कौशल विकास और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता और समग्र ढांचा प्रदान करती है।
IRCA (एकीकृत नशा मुक्ति केंद्र)	सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्र, जहाँ नशा पीड़ितों को निशुल्क परामर्श, डी-एडिक्शन (de-addiction) और अस्पताल में भर्ती कर इलाज की सुविधा मिलती है।
ODIC (आउटरीच एंड ड्रॉप-इन सेंटर्स)	यह उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में युवाओं को शुरुआती परामर्श, सुरक्षित माहौल और स्क्रीन सेवा प्रदान करते हैं।
CBO (कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन)	कम उम्र के बच्चों और किशोरों में नशे की लत को रोकने के लिए साथी/मित्र (Peer Group) के माध्यम से मार्गदर्शन देने की योजना।
ATF (एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज)	सरकारी अस्पतालों (जैसे AIIMS और जिला अस्पतालों) में स्थापित विशेष नशा मुक्ति इकाइयां।

सहायता और संपर्क सुविधा

- **राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर: 14446** *(टोल-फ्री नंबर, जिस पर मुफ्त परामर्श और नज़दीकी नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है)*

महत्वपूर्ण तथ्य

Manipur polls may be hit if Naga-Kuki violence continues, says Deputy CM

Losii Dikho, who is a member of the Naga People's Front, says Naga legislators are prepared to take 'extreme steps' if no action is taken on their concerns, including their demand for the removal of Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen, a BJP MLA belonging to the Kuki community

Vijaita Singh
NEW DELHI

Continuing Naga-Kuki violence in the hill districts of Manipur will make it difficult to conduct elections to the State Assembly next year, Manipur Deputy Chief Minister Losii Dikho said on Thursday, indicating that Naga legislators may reconsider their support to the Bharatiya Janata Party-led government if their concerns are not addressed, including their demand for the removal of fellow Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen.

Mr. Dikho is a member of the Naga People's Front (NPF) which is allied with the ruling BJP in Manipur, while Ms. Kipgen is a BJP MLA from the Kuki community. Chief Minister Khemchand Singh is from the Meitei community.

In an interview with *The Hindu*, Mr. Dikho said that Central security forces had been unable to prevent the attacks, noting that he had sent several SOS messages to the Director-General of Police a day earlier, as Naga villages in Kangpokpi were surrounded by armed groups.

Mr. Dikho, who recently led a group of nine Naga MLAs in writing to Union Home Minister Amit Shah seeking Ms. Kipgen's removal, said the current situation had become untenable and accused "Kuki militant groups" of carrying out attacks on Naga civilians.

The Home Minister is yet to respond to their memorandum, he said.

"If it continues like this, election will be very difficult, especially in the hills," Mr. Dikho said, adding that the legislators were prepared to take "extreme steps" if no action was taken on their representation to the Centre.

His remarks comes amid a renewed wave of violence between the Naga and Kuki communities over the past 10 days.

At least seven people from the two communities have been killed over the past week in Kangpokpi district, where they live in close proximity.

The incidents add another dimension to the ethnic violence that initially erupted in the State on May 3, 2023 between the Meitei and Kuki-Zo people.

Manipur Deputy Chief Minister Losii Dikho says security forces have been unable to prevent the attacks. ANI

Deputy CMs feud

Mr. Dikho alleged that the latest round of violence began after a Naga youth was assaulted in Ukhrul district on February 7 and subsequently escalated into a broader conflict. He said that six Nagas had been abducted and killed by cadres of the Kuki National Front (KNF-P), an insurgent group now under the Suspension of Operations (SoO) agreement with the Centre. Noting that the group is headed by Ms. Kipgen's husband, Thangboi Kipgen, Mr. Dikho questioned her silence following the incident.

"We were given the responsibility of restoring peace after the popular government was reinstated. While efforts were being made to reach out to all communities, she did not engage with the affected people or play a role in reducing tensions. She refused to take calls after the Nagas were abducted [on May 13] and instead switched off her phone," Mr. Dikho said.

The NPF leader said relations between him and Ms. Kipgen had broken down following the killings and claimed that she had been attending Cabinet meetings virtually.

NRC before Census

While supporting the Chief Minister's efforts to restore normalcy, Mr. Dikho said the new violence threatened to undermine recent peace initiatives. He also renewed criticism of the SoO arrangement, alleging that some militant groups were operating outside designated camps and continuing armed activities.

Asked about the reasons for the ongoing Naga-Kuki conflict, Mr. Dikho attributed it to longstanding disputes over land ownership, demographic changes, and illegal immigration.

Echoing demands raised by several Meitei groups and other civil society organisations, he supported the call to update the National Register of Citizens (NRC) before a full Census exercise is conducted in the State.

Asked why the presence of Central forces such as the Assam Rifles, CRPF and BSF had not been able to prevent the violence, Mr. Dikho said, "Some sections of people accuse some security people like Assam Rifles; I do not accept that. But for security people, as of now, the handicap is that they want to protect both sides – the Nagas and the Kukis. So if there is a firing, they cannot intervene easily... even to go to the remotest villages, to the terrain, there is no proper road."

NSCN-IM training

On allegations that the National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah (NSCN-IM) was arming and training Naga village volunteers, Mr. Dikho acknowledged that the group had provided some self-defence training to villagers amid the ongoing Naga-Kuki tensions, but denied knowledge of any arms supply.

He argued that such training was intended to help Naga villages protect themselves in areas where residents felt vulnerable to militant attacks, adding that communities had resorted to self-defence because security forces were often unable to reach remote locations quickly.

YouTube Homework

- राष्ट्रपति शासन - 356
  - संवैधानिक

महत्वपूर्ण तथ्य

- मणिपुर का जातीय संघर्ष (Ethnic Conflict) भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। नीचे इस संघर्ष के प्रमुख पहलुओं, कारणों और मणिपुर के राजनीतिक ढांचे का पूरा विवरण दिया गया है।

1. मणिपुर संघर्ष: कौन-कौन से समूह शामिल हैं?

- यह मुख्य रूप से दो प्रमुख समुदायों के बीच का संघर्ष है:
- **मैतेई (Meitei) समुदाय:**
  - **आबादी और क्षेत्र:** राज्य की कुल आबादी का लगभग 53%। ये मुख्य रूप से मणिपुर की **इम्फाल घाटी (Imphal Valley)** में रहते हैं (जो पूरे राज्य के क्षेत्रफल का केवल 10% है)।
  - **धर्म व दर्जा:** अधिकांश मैतेई हिंदू हैं (कुछ मुस्लिम भी हैं जिन्हें मैतेई पंगल कहा जाता है)। इन्हें वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त है।
- **कुकी-जो (Kuki-Zo) समुदाय:**
  - **आबादी और क्षेत्र:** राज्य की आबादी का लगभग 16-20% (नगा समुदाय के साथ मिलकर पहाड़ियों की आबादी ~40% बनती है)। ये मुख्य रूप से मणिपुर के **पहाड़ी जिलों (Churachandpur, Kangpokpi आदि)** में रहते हैं।
  - **धर्म व दर्जा:** अधिकांश कुकी ईसाई हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त है।

2. संघर्ष क्यों हो रहा है?

- यह हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जिसके पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:
- **ST दर्जे की मांग (Immediate Trigger):**
  - मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिफारिश की थी कि मैतेई समुदाय को भी ST (अनुसूचित जनजाति) का दर्जा देने पर विचार किया जाए।
  - कुकी और नगा जनजातियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क है कि मैतेई पहले से शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में मजबूत हैं; अगर उन्हें ST दर्जा मिला, तो वे पहाड़ियों में जनजातियों की जमीनों पर भी अधिकार कर लेंगे।
- **भूमि और जनसांख्यिकी (Land & Demographics):**
  - मौजूदा कानूनों के तहत गैर-जनजातीय (जैसे मैतेई) लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी और अन्य जनजातियां घाटी में जमीन खरीद सकती हैं। मैतेई समुदाय इसे अपने साथ असमानता मानता है।
- **अवैध घुसपैठ और अफीम की खेती (Illegal Immigration & Poppy Cultivation):**
  - राज्य सरकार ने पहाड़ियों में अवैध म्यांमार शरणार्थियों और आरक्षित वनों में अफीम (Poppy) की अवैध खेती के खिलाफ अभियान चलाया।
  - कुकी समुदाय का आरोप था कि इस अभियान के बहाने उन्हें उनकी पैतृक जमीनों से बेदखल किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. मणिपुर का राजनीतिक ढांचा (Political Structure)

- मणिपुर भारत का एक पूर्ण राज्य है, जिसका शासन भारतीय संविधान के तहत चलता है:
- **विधानसभा (Legislative Assembly):** मणिपुर विधानसभा में कुल **60 सीटें** हैं।
  - **घाटी (Valley) की सीटें:** 40 सीटें (जिन पर मैतेई बहुल आबादी का प्रभाव रहता है)।
  - **पहाड़ी (Hills) की सीटें:** 20 सीटें (जो ST समुदाय—कुकी और नगा के लिए आरक्षित हैं)।
- **अनुच्छेद 371C (Article 371C):** भारत के संविधान का यह विशेष प्रावधान मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय हितों की रक्षा के लिए 'हिल एरिया कमेटी' (Hill Areas Committee) के गठन का अधिकार देता है।

4. मणिपुर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां

पार्टी का नाम	राजनीतिक स्थिति और प्रभाव
भारतीय जनता पार्टी (BJP)	राज्य की सत्तारूढ़/प्रमुख पार्टी। एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) भाजपा से ही मुख्यमंत्री हैं। पार्टी का घाटी और पहाड़ियों दोनों में जनाधार है, हालांकि हालिया संकट के बाद कुकी विधायकों के साथ मतभेद बढ़े हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी। मणिपुर में लंबे समय तक शासन करने का इतिहास रहा है।
नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)	पूर्वोत्तर की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी (मुकुल संगमा/कॉनराड संगमा की पार्टी), जो एनडीए (NDA) गठबंधन का हिस्सा रही है।
नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF)	नगा बहुल पहाड़ी इलाकों में मजबूत उपस्थिति। यह भी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रही है।
कुकी पीपुल्स एलायंस (KPA)	कुकी समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टी।

महत्वपूर्ण तथ्य

वर्तमान स्थिति का सार

- इस संघर्ष के कारण राज्य में घाटी (मैतेई) और पहाड़ी (कुकी) क्षेत्रों का एक तरह से **भौगोलिक और सामाजिक विभाजन (Complete Separation)** हो गया है। कुकी समुदाय के प्रतिनिधि केंद्र सरकार से अपने लिए 'अलग प्रशासनिक व्यवस्था' (Separate Administration) की मांग कर रहे हैं, जबकि मैतेई समुदाय मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) को बनाए रखने पर अड़ा हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

Bar Council has no power to punish students: SC

- Court says the BCI, its head lack jurisdiction over students; only universities can discipline them
- SC rebukes BCI's attempt to intimidate NALSAR students who opposed CJI as chief guest at event
- The BCI's disciplinary powers under Advocates Act, 1961, are limited to advocates, court adds

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Thursday declared that the Bar Council of India (BCI) and its Chairperson, Manan Kumar Mishra, lack jurisdiction to discipline or penalise law students, rebuking the regulatory body's attempts to intimidate NALSAR students exercising their constitutional right to protest.

The court insisted on clarifying the limits of the BCI's powers though the latter had revoked its August 13 letters to NALSAR administration to launch an inquiry against the students and to the State Bar Councils to block their professional enrolment.

The students had protested against having Chief Justice Surya Kant as chief guest at their convocation following his oral comments in court comparing youth to "cockroaches" and "parasites".

Right to dissent

A three-judge Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant said the order, drawing the boundary for the Bar Council, was designed to safeguard university space and students' right to freely express dissent against future attempts to breach.

> On an in-depth consideration of the issue, we are of the opinion that the Advocates Act, 1961 does not confer, expressly or impliedly, any power on the Bar Council of India and State Bar Councils to take any disciplinary or punitive action against law students
>
> SUPREME COURT

"The BCI has no jurisdiction or statutory competence as regards students. That is for their universities," Chief Justice Kant observed.

"On an in-depth consideration of the issue, we are of the opinion that the Advocates Act, 1961, does not confer, expressly or impliedly, any power on the Bar Council of India and State Bar Councils to take any disciplinary or punitive action against law students," the top court recorded in the order.

Mr. Mishra, who was present, said that the BCI had a role in regulating legal education.

But the court said the BCI could step in only after enrolment.

Its disciplinary powers under the Advocates Act, 1961, were, obviously, limited to registered advocates.

"Till then, BCI did not come into the picture... To say a student will not be enrolled..." Justice Joymalya Bagchi said, leaving the sentence unfinished.

The apex court was hearing a petition filed by two former NALSAR graduates, represented by senior advocate K. Parameshwar and advocate Rupali Samuel, seeking legal action against the BCI and the chairperson for threatening the 2026 batch of NALSAR students.

Freedom of speech

The petition said that the Bar Council's letters had created a chilling effect on the freedom of speech and the freedom of association among students.

Mr. Mishra said that letters issued to NALSAR and State Bar Councils were withdrawn "within one hour".

He said there was no reason for further cause of action, and the controversy should be given a quietus.

However, the court agreed with Mr. Parameshwar that the court should protect students in the future against any such violation of their rights by bodies acting without jurisdiction.

Such a situation should never arise, the senior counsel said.

It clarified that only the parent university or the competent authority under the law has any disciplinary power over students.

The Bench said the August 13 letters of the BCI were "obsolete".

- SC

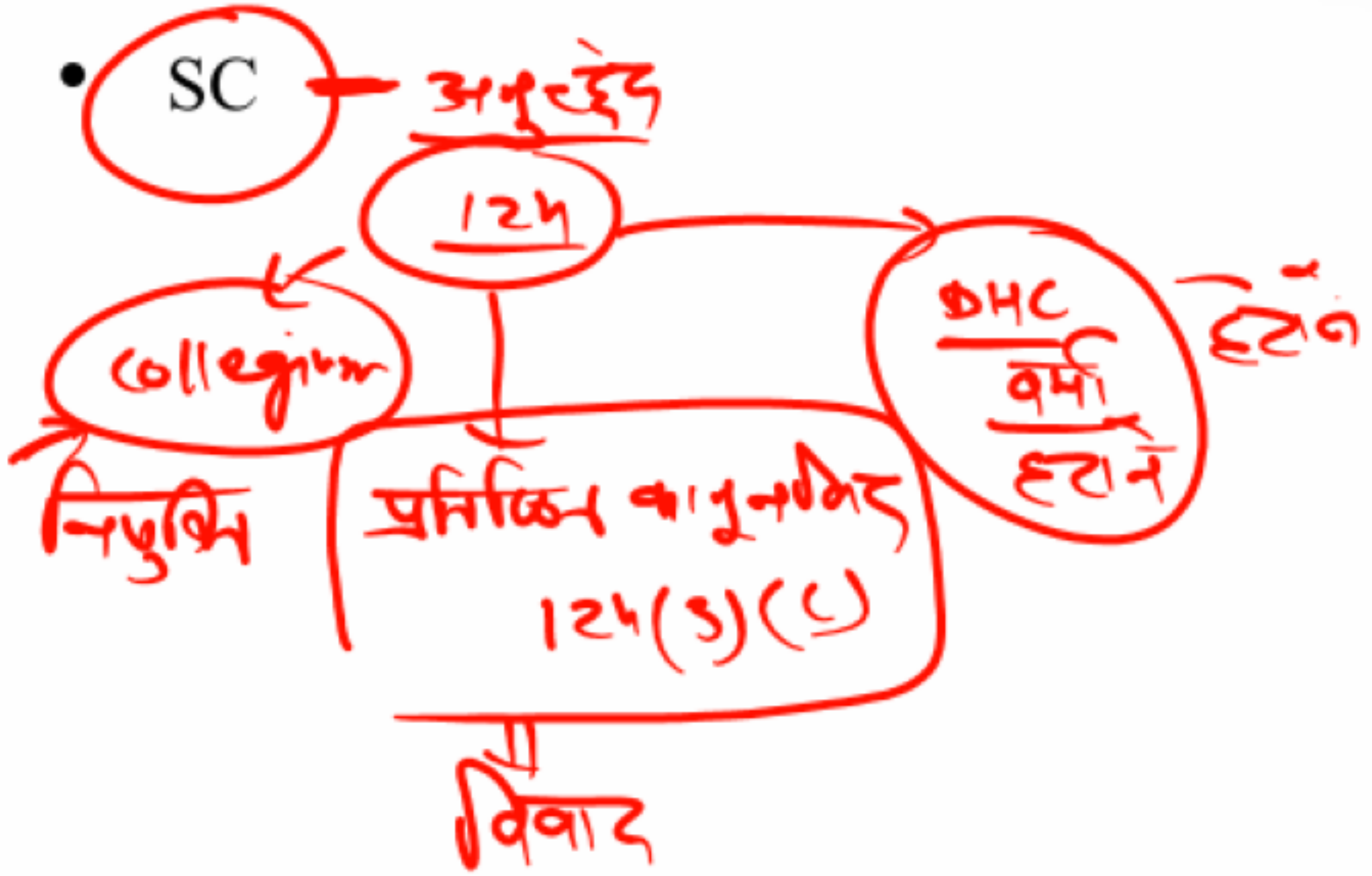

महत्वपूर्ण तथ्य

- **Advocates Act, 1961** भारत में वकीलों और कानूनी पेशे (Legal Profession) को विनियमित करने वाला मुख्य केंद्रीय कानून है। इस अधिनियम ने देश में एक एकीकृत कानूनी प्रणाली बनाई और वकीलों के पंजीकरण, आचार संहिता तथा अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए **बार काउंसिल** का गठन किया।

1. Advocates Act, 1961 का उद्देश्य

- **एक एकीकृत वर्ग (Single Class of Practitioners):** इस कानून से पहले भारत में अलग-अलग प्रकार के कानूनी व्यवसायी होते थे (जैसे Pleader, Mukhtar, Barrister, Attorney)। 1961 के अधिनियम ने इन सभी को समाप्त कर **"अधिवक्ता" (Advocate)** का केवल एक ही एकीकृत वर्ग बनाया।
- **स्वायत्त संस्थाएं बनाना:** कानूनी पेशे को नियंत्रित करने का अधिकार अदालतों या सरकार के बजाय स्वयं वकीलों की चुनी हुई संस्थाओं (Bar Councils) को दिया गया।
- **अधिकार:** देश की किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकारी के समक्ष वकालत करने का अधिकार प्रदान करना।

2. मुख्य वैधानिक निकाय (Statutory Bodies)

- इस अधिनियम के तहत दो स्तरों पर गवर्निंग बॉडीज का गठन किया गया है:

निकाय (Body)	कार्य और संरचना
1. Bar Council of India (BCI)	• यह पूरे देश के लिए शीर्ष निकाय है। • कानूनी शिक्षा के मानक (Standards) तय करता है और लॉ कॉलेजों को मान्यता देता है। • अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचार संहिता (Code of Ethics) बनाता है।
2. State Bar Councils (SBC)	• प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक स्टेट बार काउंसिल होती है। • राज्य में वकीलों का पंजीकरण (Enrollment) करना और रोल (Roll) बनाए रखना। • वकीलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. महत्वपूर्ण धाराएं

- **Section 16 (Senior & Other Advocates):** यह अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित करता है—**वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate)** और **अन्य अधिवक्ता**। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट किसी वकील की क्षमता और अनुभव के आधार पर उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे सकते हैं।
- **Section 24 (Qualification for Enrollment):** एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होने की शर्तें:
  - भारत का नागरिक होना।
  - न्यूनतम 21 वर्ष की आयु।
  - BCI द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री (LL.B.)।
  - वर्तमान में: All India Bar Examination (AIBE) पास करना अनिवार्य है।
- **Section 29 & 30 (Right to Practice):** केवल पंजीकृत अधिवक्ताओं को ही भारत की सभी अदालतों (सुप्रीम कोर्ट सहित), ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी में केस लड़ने का कानूनी अधिकार है।
- **Section 35 (Disciplinary Powers):** यदि कोई वकील पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया जाता है, तो स्टेट बार काउंसिल उनका लाइसेंस निलंबित (Suspend) या रद्द (Cancel) कर सकती है।

4. अधिवक्ताओं के कर्तव्य

- अधिनियम के तहत BCI द्वारा वकीलों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं:
- **अदालत के प्रति कर्तव्य:** अदालत का सम्मान करना, न्यायाधीश को गुमराह न करना और अनुचित साधनों का प्रयोग न करना।
- **क्लाइंट के प्रति कर्तव्य:** क्लाइंट की गोपनीयता (Confidentiality) बनाए रखना, उनके हितों की रक्षा करना और उनसे अनुचित फीस न वसूलना।
- **विरोधी पक्ष के प्रति कर्तव्य:** विरोधी वकील या पार्टी को सीधा संपर्क कर गुमराह न करना।
- **निष्कर्ष**
- Advocates Act, 1961 भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कानूनी पेशे में व्यावसायिकता (Professionalism), स्वतंत्रता और उच्च मानकों को बनाए रखने का कार्य करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

2027 Prelims

प्रश्न. Advocates Act, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India - BCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Advocates Act, 1961 ने प्लीडर (Pleaders) और बैरिस्टर जैसे कानूनी व्यवसाइयों के विभिन्न वर्गों को समाप्त कर 'अधिवक्ता' (Advocate) का केवल एक एकीकृत वर्ग बनाया।
2. भारत के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के समक्ष वकालत करने का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जो किसी राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हैं।
3. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है जो देश में कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करती है और लॉ कॉलेजों को मान्यता प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

महत्वपूर्ण तथ्य

Congress questions GDP revision, asks government to explain methodology

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Congress on Thursday posed four questions to the government over the latest GDP estimates, seeking an explanation for a cumulative downward revision of ₹43 lakh crore in the estimated size of the Indian economy over the past four years and questioning the methodology used to calculate real growth.

Congress leader Jairam Ramesh asked why GDP estimates for all four years since 2022-23 had been revised substantially downwards, what components of the new methodology had driven the changes, who had been consulted in framing it and why the deflator used for calculating real GDP appeared to understate the impact of inflation.

"How has a change in methodology produced such a large drop in the estimated size of the Indian economy," he asked.

Jairam Ramesh

The questions came days after the government highlighted 7.8% real GDP growth in the April-June 2026 quarter. Mr. Ramesh said the figure required closer scrutiny and alleged that the revisions had made the growth rate appear stronger than it was.

Garg's analysis

He pointed to repeated revisions to the GDP estimate for April-June 2025, which had brought the figure down from about ₹86 lakh crore to ₹80 lakh crore.

Citing calculations by former Finance Secretary Subhash Chandra Garg, Mr. Ramesh said nominal growth in the latest quarter would have been closer to 2.6%, instead of the reported 10.3%, had the earlier base not been revised downwards.

"India's GDP growth is being inflated by a deflator that does not reflect the inflation faced by ordinary Indians," Mr. Ramesh said, referring to the gap between the GDP deflator and retail and wholesale inflation.

He also alleged that the new GDP series had reduced nominal GDP estimates for almost every quarter over the four-year period, resulting in an aggregate reduction of ₹43 lakh crore. The government needed to explain how a change in methodology could result in such a large reduction in the estimated size of the economy.

Mr. Ramesh also questioned the GDP deflator, which stood at 2.5% for the quarter, against retail inflation of 3.9% and wholesale inflation of 9.4%. The widening gap raised questions about whether the deflator adequately captured the inflation faced by households, he argued.

He cited concerns raised by former Chief Economic Adviser Arvind Subramanian and the IMF over India's national accounts, arguing that the Centre needed to provide greater transparency on the methodology underlying the estimates.

In a sharp attack on Prime Minister Narendra Modi, Congress leader K.C. Venugopal said Mr. Modi was "a creator of a manipulated world". "Let him live in that world but the reality is quite different," he said.

RM → moring 9
Night 9
Topic
GDP Growth 7.8%
उसको देख लो।

YouTube Homework

- GDP
- GVA

महत्वपूर्ण तथ्य

Cong. chief writes to Nadda, questions delay in action over 'purification' ritual

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Congress president Mallikarjun Kharge on Thursday said the *shuddhikaran* (purification) of the Ramlila ground in Haldwani area of Uttarakhand, where he had addressed a political rally, amounted to practising "untouchability", and said his party would approach Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan over the issue.

On September 2, Mr. Kharge, who is the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, wrote to Union Minister and Leader of the Rajya Sabha J.P. Nadda, urging him to direct Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami to ensure that an FIR was registered against those responsible for the alleged purification ritual.

In his letter, which was released on Thursday, Mr. Kharge recalled that he had raised the matter in the Rajya Sabha on August 13 and that Mr. Nadda had assured the House that the incident would be investigated and strict action taken against those found guilty. The Rajya Sabha Chairman had also expressed his grief over the incident, he said.

> This issue... is deeply connected to the sentiments of crores of people who confront this harsh reality on a daily basis
>
> **MALLIKARJUN KHARGE**
> Congress president

'No FIR yet'

"Even after 24 days of this incident, not even an FIR has been filed against the organisations and individuals involved in this heinous act," he said.

He linked the incident to the history of caste discrimination, recalling that during the Mahad Satyagraha, when B.R. Ambedkar drank water from a public tank, caste Hindus had subsequently performed a purification ritual using *gomutra* and *gobar*.

"This issue transcends my personal self or the office of the Indian National Congress president; it is deeply connected to the sentiments of crores of people who confront this harsh reality on a daily basis," he said in his letter.

The Congress president said the ritual at the Ramlila Maidan, following his August 8 rally, was contrary to the spirit of the Constitution and human values. "This is an incident of untouchability, it is not just about purification," he told presspersons here.

Mr. Kharge also questioned the silence of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah on the issue. "Whenever something wrong happens, they remain silent," he said, citing the alleged theft of donations to the Ram Temple, and atrocities against Dalits as the other instances.

He also defended the Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, who had criticised the purification ritual. An FIR was subsequently registered against Mr. Gandhi over his remarks.

Congress leader K.C. Venugopal said Mr. Gandhi will not be intimidated by cases against him.

YouTube Homework

- Untouchability

अस्पृश्यता - अनुच्छेद-17

SC/ST - 1989

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम - 1976

महत्वपूर्ण तथ्य

No defence ties with Pak., Belgium assures India

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

Belgium has assured India that it will not pursue defence cooperation or provide technological assistance to Pakistan, sources in the government said on Thursday, following bilateral talks between Defence Minister Rajnath Singh and Belgium's Defence Minister Theo Francken.

According to the sources, during the meeting in New Delhi, Mr. Singh specifically raised India's concerns over the possibility of Belgian defence technology or expertise being extended to Pakistan. Mr. Francken assured the Indian side that Belgium stood firmly with India and that there was "no question" of defence cooperation with Pakistan.

The assurance assumes significance as India has been raising concerns with its international partners over the transfer of defence technologies and military equipment that could strengthen Pakistan's military capabilities.

Union Minister Rajnath Singh holding a bilateral meeting with his Belgium counterpart Theo Francken in New Delhi on Thursday. ANI

During the interaction, the two sides reviewed the entire spectrum of bilateral defence and industrial cooperation. The Ministers agreed to expand engagement through defence cooperation dialogue, high-level visits, training and capacity building.

They also discussed regional peace and security and acknowledged the need for greater maritime security collaboration in the Indo-Pacific. Both sides reiterated that the India-Belgium partnership is based on shared values, mutual trust and respect.

The bilateral meeting was held on the sidelines of talks between Prime Minister Narendra Modi and Belgian Prime Minister Bart De Wever, who is on an official visit to India.

Earlier, Mr. Francken and Minister of State for Defence Sanjay Seth addressed the India-Belgium Defence CEOs Roundtable and B2B Meetings here.

Emphasising the potential for deeper industrial collaboration, the Belgian Defence Minister called for joint efforts to strengthen the armed forces of both countries in an evolving security environment.

India and Belgium ramp up bilateral defence cooperation

After meeting his Belgian counterpart, Prime Minister calls for ending conflicts in Ukraine and West Asia through dialogue; three government-level defence agreements signed; two sides also announce the establishment of a fast trade mechanism

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Thursday called for dialogue and diplomacy to end the ongoing conflicts in Ukraine and West Asia.

Mr. Modi made the remarks while welcoming Belgian Prime Minister Bart De Wever here, where the two sides ramped up bilateral defence cooperation by signing three government-level defence agreements.

Belgian sources informed that at least 10 private defence agreements will be sealed during the visit that will include production of Belgian military items such as rockets in India.

"Whether it is Ukraine or West Asia, we support all efforts aimed at an early end to conflicts and the restoration of peace. And

Boosting ties: Prime Minister Narendra Modi with Prime Minister of Belgium Bart De Wever in New Delhi. SUSHIL KUMAR VERMA

eliminating terrorism in all its forms and manifestations is our shared commitment," Mr. Modi said in his remarks after he and Mr. De Wever discussed global and regional issues.

Paid tributes

The two leaders also paid tributes to the more than 9,000 Indian soldiers who perished in the Flanders Fields during the First World War. A Joint Statement issued at the end of the discussions announced that the two leaders called for "safety and security of maritime routes and maintaining safe and unimpeded maritime shipping" in the context of the conflicts in West Asia and Ukraine.

The Belgian dignitary expressed support to India's campaign against cross-border terrorism and condemned the Pahalgam terror attack.

In his remarks at an event organised by the CII (Confederation of Indian Industry), the Belgian leader described the current global situation as "turbulent" and called for free trade and end to unilateral imposition of tariffs.

The two governments signed a Letter of Intent of Defence Cooperation, an MoU between Belgian Security and Defence Industry and Society of Indian Defence Manufacturers, and an MoU between the Central Bureau of Investigation and Belgium Federal Police on cooperation in combating transnational organised crime, cyber-crime and related matters.

"Our security does not stop at our borders. That is why we need to work more closely with strong partners such as India – militarily, technologically and industrially," said Belgian Defence Minister Theo Francken.

On this occasion, India announced that a Defence Attache will be appointed at the Indian Embassy in Brussels. The visit included defence partnerships between Belgian and Indian defence majors. "Today, India and Europe are speaking the language of trade with renewed conviction, a language of peace, of progress and of prosperity," said Mr. De Wever.

The two sides announced the establishment of a fast trade mechanism that will deal with trade and investment and announced that bilateral trade will be doubled in the next five years. They also announced the establishment of Consular Dialogue between New Delhi and Brussels.

YouTube Homework

- India & Other Countries

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत और बेल्जियम के बीच रक्षा, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और व्यापार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी के समझौतों का आदान-प्रदान हुआ है।

हालिया उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं और समझौतों के मुख्य बिंदु:

- **रक्षा सहयोग (Defence Cooperation):** दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र (Letter of Intent - LoI) पर हस्ताक्षर किए।
- **सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी:** बेल्जियम का 'इमेक' (imec - Interuniversity Microelectronics Centre) सेमीकंडक्टर R&D का वैश्विक केंद्र है। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, रिसर्च और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर समझौता हुआ।
- **ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा:** हरित ऊर्जा (Green Energy) संक्रमण, क्लीन-टेक और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान और निवेश का करार।
- **हीरा व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला:** एंटवर्प (Antwerp, बेल्जियम) और सूरत/मुंबई (भारत) के बीच रफ और पॉलिस्ड डायमंड के पारदर्शी और सतत व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति।
- **पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (Port Logistics):** बेल्जियम के एंटवर्प-ब्रुग्स पोर्ट और भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच लॉजिस्टिक्स, ग्रीन पोर्ट मैनेजमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर साझेदारी।

महत्वपूर्ण तथ्य

Iran attacks U.S. bases in West Asia despite Trump's threats of strikes

Tehran's military claims it hit Kuwait's Ahmed al-Jaber Air Base; Kuwait says its forces intercepted a missile and drone strike coming from Iran, and condemned the attack as a 'threat' to the country's 'security and a grave breach of international law'

Agence France-Presse
TEHRAN

Iran attacked U.S. military bases in Kuwait on Thursday, despite President Donald Trump threatening further strikes in a renewed flare-up six months into the war.

Mr. Trump said his military was prepared to attack Iran "any time we want" after extensive U.S. bombardment of sites across the country left at least 19 Iranians dead between Tuesday and Wednesday.

Tehran has once again retaliated with strikes across West Asia this week, saying it targeted U.S. bases and forces in the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Jordan and Iraq's Kurdistan region.

Rubble lies around damaged houses following a reported attack near a wedding gathering in Iran on Wednesday. REUTERS

Iran's pummelling of U.S. military targets across the region came after a U.S. attack that hit a wedding in the country's south, prompting fury from Tehran. The Iranian Red Crescent said shrapnel from the missile attack in the coastal town of Kuhestak killed four persons, including a child, and wounded more than 50.

Iran's Revolutionary Guards chief Ahmad Vahidi vowed on Thursday to avenge the four killed. "The pure blood of these oppressed martyrs... will not go unanswered and will definitely be avenged".

U.S. Central Command (CENTCOM) spokesperson Tim Hawkins said "the U.S. military never targets civilians, unlike the IRGC", referring to Iran's Revolutionary Guards.

Kuwait's army on Thursday said it was intercepting a missile and drone attack from Iran, with the Iranian army saying it hit "the Ahmad al-Jaber Air Base in Kuwait with missiles and drones".

Iran's army also said it struck Al Minhad Air Base in the United Arab Emirates, but the Gulf country reported no such attack.

Kuwait called the attacks "a direct threat to its security and stability, and a grave breach of the rules of international law".

Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday voiced confidence that Iran's Islamic republic could soon fall, saying it was weaker than ever as the United States resumed attacks.

महत्वपूर्ण तथ्य

'Supersized' El Nino to be strongest ever recorded: UN

Reuters
GENEVA

World Meteorological Organisation Secretary-General Celeste Saulo, left, attend a press conference in Geneva on Thursday. AFP

The El Nino weather phenomenon is set to intensify further into 2027 and could be the strongest ever, raising risks of extreme weather into next year, the World Meteorological Organisation said on Thursday.

The UN weather agency said its forecasts showed a near 100% likelihood that El Nino would persist through February 2027, fuelled by exceptionally warm Pacific Ocean temperatures. This is the first time it has expressed such a degree of certainty, the WMO said.

"If this trajectory continues, it may be stronger than anything since our monitoring began. So literally off the charts," WMO Secretary-General Celeste Saulo told a Geneva press conference.

El Nino is a periodic warming of sea surface temperatures in the eastern Pacific caused by weakening trade winds. It occurs every two to seven years and tends to last up to 12 months, causing intense rains and droughts across Latin America.

A very strong El Nino can significantly shift rainfall and temperature patterns worldwide, and fuel extreme weather, such as droughts and typhoons.

The WMO said it was stepping up preparedness and early warning efforts in preparation to allow states to take early action.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization - WMO)** संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जो मौसम (Weather), जलवायु (Climate), और जल संसाधनों (Water Resources) के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है।

1. मुख्य विवरण (Key Overview)

- **स्थापना:** 23 मार्च 1950 (इसी कारण हर साल 23 मार्च को **'विश्व मौसम विज्ञान दिवस'** मनाया जाता है)।
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड (Geneva, Switzerland)।
- **सदस्य देश:** 193 देश और क्षेत्र (भारत भी इसका संस्थापक/सक्रिय सदस्य है)।
- **मूल निकाय (Parent Agency):** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (UN ECOSOC)।

2. प्रमुख कार्य और उद्देश्य

- **वैश्विक मौसम अवलोकन:** दुनिया भर के मौसम स्टेशनों, उपग्रहों और समुद्र विज्ञान प्रणालियों के आंकड़ों का आदान-प्रदान और समन्वय करना।
- **जलवायु परिवर्तन पर निगरानी:** वैश्विक तापमान, ग्रीनहाउस गैसों के स्तर, और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि पर नियमित वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना।
- **समय पूर्व चेतावनी (Early Warning Systems):** चक्रवात, बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरों (Heatwaves) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करना ताकि जन-धन की हानि कम हो सके।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** दुनिया भर में पेयजल और जल विज्ञान (Hydrology) से जुड़ी नीतियों में तकनीकी सहायता देना।

3. प्रमुख रिपोर्ट और प्रकाशन

- WMO द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC) के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं:
- **State of the Global Climate Report:** वैश्विक तापमान और जलवायु संकेतकों पर वार्षिक रिपोर्ट।
- **Greenhouse Gas Bulletin:** वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर पर रिपोर्ट।
- **Air Quality and Climate Bulletin:** वायु गुणवत्ता और जलवायु के अंतर-संबंधों पर विश्लेषण।

4. महत्वपूर्ण पहल

- **IPCC की सह-स्थापना:** WMO ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के साथ मिलकर 1988 में **IPCC** (Intergovernmental Panel on Climate Change) की स्थापना की थी, जो जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार करता है।
- **Early Warnings for All (EW4All):** संयुक्त राष्ट्र की इस पहल का लक्ष्य 2027 तक दुनिया के हर व्यक्ति को मौसम की खतरनाक घटनाओं से बचाने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के दायरे में लाना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Iceland sticks to U.S. security umbrella despite Trump's Greenland threats

Agence France-Presse
REYKJAVIK

Iceland has regained strategic geopolitical importance as tensions rise in the Arctic, but with no military it still relies on Washington for its security – despite the unpredictability of U.S. President Donald Trump.

By rejecting a resumption of its suspended European Union membership talks in a referendum last weekend, Icelanders voted in favour of maintaining the status quo.

This involves combining European economic integration – it already has access to the single market through the European Economic Area – with Atlanticism in defence matters.

Iceland has never had a military since gaining independence in 1944. Instead, it has depended on NATO, of which it is a founding member, as well as a 1951 bilateral defence agreement with the U.S.

Mr. Trump's repeated threats to take over control of Greenland, a Danish autonomous territory located fewer than 300 kilometres from Iceland, and his trade showdown with Canada have rattled Iceland, although it remains steadfast in maintaining its close ties to the U.S. "Of course, the political rhetoric is concerning. But it's important also to try to strengthen the relationship," Iceland's Chief of Defence Jonas Allansson told *AFP*.

After the end of the Cold War, the U.S. closed its Keflavik base in 2006, about 30 kilometres as the crow flies from Reykjavik. It gradually returned from the mid-2010s onward, amid renewed tensions with Moscow following the annexation of Crimea.

The U.S. Navy regularly deploys maritime patrol aircraft over Iceland, while NATO members police its skies and the Alliance ramps up military exercises.

The North Atlantic island is a key outpost in the so-called GIUK gap, the strategic corridor between Greenland, Iceland and the United Kingdom through which Russia's Northern Fleet submarines must pass to reach the Atlantic via the Norwegian Sea.

"The situation that we have today is quite comparable" to that during the Cold War, Mr. Allansson said. "In some ways there is more uncertainty in the equation now because of the policy of the Russian regime."

Security ties: Iceland has no military of its own and relies on NATO and a 1951 defence pact with the U.S. REUTERS

All the more so as China also shows growing interest in the Arctic, whose resources and sea routes are becoming more accessible as climate change causes the ice pack to melt.

'Atlantic watchtower'

"Today, supposed Russian and Chinese research vessels are conducting joint patrols [in the Arctic] but we all know they're not up here counting puffins," NATO's Supreme Allied Commander in Europe, Alexus Grynkewich, said during the alliance's Northern Viking exercise in Iceland in late August. Presenting itself as a "watchtower" in the North Atlantic, Iceland aims to play the role of "force multiplier" in NATO, investing in cybersecurity and infrastructure to facilitate allies' presence and transit in the region.

Reykjavik plans to devote 1.5% of its gross domestic product (GDP) to these efforts by 2035. But the plans have met with some opposition.

A leading figure in Iceland's longstanding anti-military movement, Stefan Palsson, told *AFP* it was "very irresponsible" of Iceland's government to open the country's doors so widely to the US and NATO. "More military infrastructure in Iceland makes it more likely, rather than less likely, that we will be dragged into conflict that basically has nothing to do with us," he said.

"It is completely clear in my mind that the U.S. military presence in Iceland has never been about the interest of Icelanders or our defence but it has always been about U.S. military interests," he added.

He fears that in a worst case scenario – which he himself judged "very unlikely" – Iceland could end up serving as a logistical support base if Washington were to resort to force to seize Greenland.

Mikaa Blugeon-Mered, a geopolitics researcher at the University of Quebec, noted that the mutual assistance clause provided for in EU treaties ultimately carried too little weight with Icelanders, compared to the guarantees offered by a superpower like the U.S.

"Joining the European Union today would not allow Iceland to simply swap its American umbrella for a European umbrella," he told AFP.

"Paradoxically, Donald Trump's threats have reinvigorated the European debate in Iceland but they have not necessarily convinced Icelanders that the European Union would offer them a better military guarantee than the set-up they already have."

महत्वपूर्ण तथ्य

आर्कटिक क्षेत्र क्या है?

- **सीमा:** यह क्षेत्र **आर्कटिक वृत्त (Arctic Circle - 66.5° N अक्षांश)** के उत्तर में स्थित है।
- **संरचना:** इसमें **आर्कटिक महासागर (Arctic Ocean)**, विशाल समुद्री बर्फ (Sea Ice), और आठ देशों के उत्तरी भूभाग शामिल हैं।
- **शामिल देश (Arctic States):** कनाडा, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का)।
- **विशेषता:** यहाँ अत्यधिक ठंड, बर्फ और प्रतिवर्ष 'मिडनाइट सन' (24 घंटे सूरज का दिखना) और 'पोलर नाइट' (24 घंटे अंधेरा) जैसी घटनाएँ होती हैं।

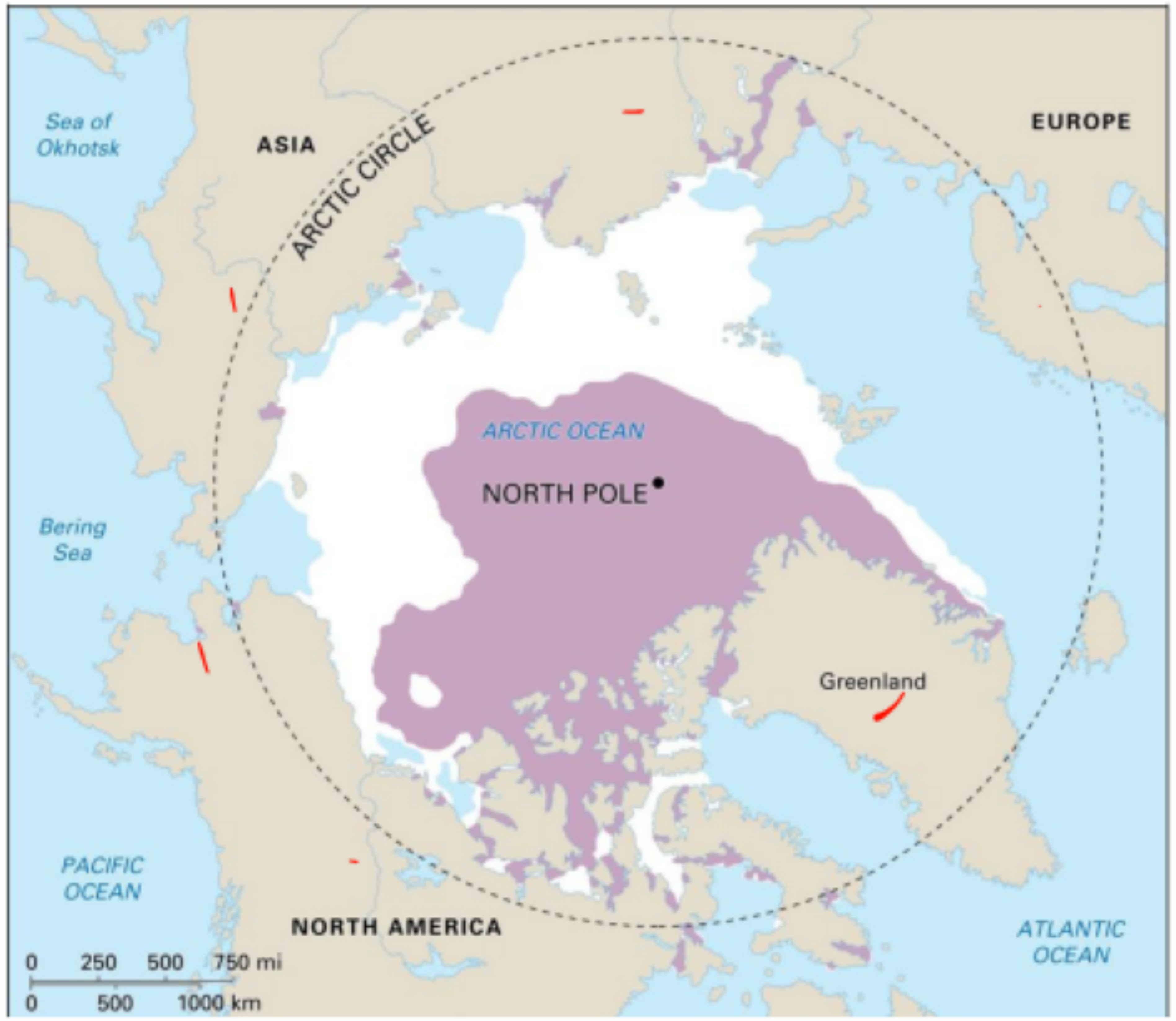

महत्वपूर्ण तथ्य

- आइसलैंडClick to open side panel for more information उत्तर-पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत और रणनीतिक द्वीपीय देश (Island Country) है।
- इसे **"अग्नि और बर्फ की भूमि" (Land of Fire and Ice)** कहा जाता है, क्योंकि यहां एक तरफ बर्फ से ढके विशाल ग्लेशियर हैं, तो दूसरी तरफ सक्रिय ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने (Geysers) और भू-तापीय (Geothermal) ऊर्जा के स्रोत हैं।

भौगोलिक स्थिति और लोकेशन

- **महासागर:** यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
- **पड़ोसी देश/क्षेत्र:**
  - इसके पश्चिम में **ग्रीनलैंड** (Greenland) है।
  - इसके पूर्व में **नॉर्वे** और दक्षिण-पूर्व में **यूनाइटेड किंगडम (UK)** व **फ़ैरो द्वीप-समूह** (Faroe Islands) हैं।
- **अक्षांश (Latitude):** यह **आर्कटिक वृत्त (Arctic Circle - 66.5° N)** के ठीक नीचे/दक्षिण में स्थित है। इसका सबसे उत्तरी द्वीप *Grímsey* इस रेखा को छूता है।
- **राजधानी: रेक्याविक (Reykjavík)** — यह दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी शहर है।

महत्वपूर्ण तथ्य

The feminist organiser and her daily rebellions

Sunalini Mathew
NEW DELHI

On her website, Gloria Steinem describes herself as a "feminist organizer", a doer, as most women are. Until the end, she hosted Talking Circles, at her New York home, where people gathered do the rough-and-tumble work of activism, but also the gentler work of community building. This "movement building" is what Steinem will always be remembered for.

The practice of gathering in a group, where everyone is heard, was inspired from India, where Steinem spent two years, after she graduated at 22, from Smith College, Massachusetts in 1956. She came to India every few years, and was closely associated with Ruchira Gupta, who founded Apne Aap Women Worldwide, a non-profit working to end sex trafficking. Steinem chaired Apne Aap's advisory board, and for Ms. Gupta, she was "a third parent."

GLORIA STEINEM (1934-2026)

Ms. Gupta says their relationship went back to the 1990s. "She had heard about my work through mutual friends and wanted to see it. I took her in an autorickshaw into the slums of Delhi, where I was organising some women. It began to rain, and I hoped the women would show up," she says. There, in front of a tumbledown building, Steinem spoke to the women about the abortion she had had in her youth. "She spoke in English; I translated, but the women connected with her story. They began to speak about their experiences with abortion."

Books and essays

With Steinem, she co-edited *As if Women Matter: The Essential Gloria Steinem Reader*, essays by Steinem, on feminist thought.

Besides this, Steinem wrote nine books, including *The Truth Will Set You Free, But First it Will Piss You Off!*, *Outrageous Acts and Everyday Rebellions*, and her memoir that is slated for release internationally in September, called *An Unexpected Life*. She was also the founder-editor of *Ms.* magazine.

Independent journalist and author, Ammu Joseph, who lives and works out of Bengaluru, remembers spending about a week as a journalism student in the *Ms.* office in 1976, four years after *Ms.* began, selling three lakh copies of its first issue.

"She debunked the whole notion of feminists being humourless and dowdy, and maybe because of her women are proud to call themselves feminists."

Ms. magazine's first issue had an illustration of a blue Kali, with eight arms, each holding an iron, hand mirror, phone, steering wheel, typewriter, frying pan, duster, and clock. It talked about issues of domestic violence, sexual harassment, and the repealing of laws that criminalised abortion.

Steinem, a product of the second-wave feminist movement, reframed abortion as "reproductive freedom". "She had the audacity to look at women's issues and at how the world is shaped by men, for men, and how women are subsidiary players in the field," says Sujata Sriram, a professor at School of Human Ecology, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Ms. Sriram notes that Steinem's influence in the Indian feminist movement is not widespread, but that a great deal of international research sprung from her ideas.

Ms. Gupta remembers a time just before the icon passed. "We were lying in bed, and she spoke about a woman in the Himalayas who had lived until 105. She joked she would too, especially to see Trump out of office." This time, Ms. Gupta jokes: "I'd like to take that up with her now."

महत्वपूर्ण तथ्य

- **ग्लोरिया स्टेनेम (Gloria Steinem)** एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार, नारीवादी (Feminist) और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
- **पहचान:** 1960-70 के दशक के 'दूसरी लहर के नारीवादी आंदोलन' (Second-Wave Feminism) की प्रमुख नेता।
- **बड़ा काम:** 1972 में महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित **'Ms. Magazine'** की शुरुआत की।
- **मुख्य योगदान:** राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, समान वेतन और प्रजनन अधिकारों (Reproductive Rights) के लिए जीवनभर लड़ाई लड़ी।
- **सम्मान:** 2013 में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान *'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम'* से सम्मानित।

Overview

- Cooperative Societies
- Namami Gange
- Nasha Mukt Bharat Abhiyan
- Manipur Crisis
- BCI
- GDP Growth rate
- Untouchability
- India-Belgium
- USA-IRAN
- WMO – El-Nino
- Iceland
- Gloria Steinem

Thank You

Result Mitra